THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Bills for consideration and passing. The Freedom of Earning Livelihood Bill, 2010, Dr. Akhilesh Das Gupta. Not present.

Now, the next Bill, The Pre-Examination Coaching Centres Regulatory Authority Bill, 2010, Shri Mohan Singh.

PRIVATE MEMBER'S BILLS – *withdrawn/under consideration*

The Pre- Examination Coaching Centres Regulatory Authority Bill, 2010

श्री मोहन सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेन्टरों के विनियमन हेतु एक विनियामक प्राधिकरण का गठन करने और तत्संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

महोदय, हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने आज यह एक गंभीर स्थिति उपस्थित हो गई है। आज लाखों की संख्या में विद्यार्थी कोटा से लेकर दिल्ली तक, नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक कोचिंग की तलाश में बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। इन कोचिंग संस्थाओं की कोई निर्धारित फीस नहीं है और कहीं-कहीं पर तो यह फीस डेढ़ लाख से लेकर तीन लाख तक है। इसका नतीजा यह हुआ कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापको का वेतन भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया है। अब प्रोफेसर वेतन 70,000 से लेकर 1,50,000 तक पाते हैं। परीक्षा की कापी जांचने और पेपर सेट करने तक यदि देखा जाए, तो आज ऐसा कोई सीनियर अध्यापक नहीं है जो भारी वेतन प्राप्त न करता हो। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वे अध्यापक अपनी कक्षाओं में जाते ही नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो बिना पढ़ाए ही पैसे लेने के अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन वही लोग अपने पढ़ाने के समय में कोचिंग में जाकर पढ़ाते हैं और उसका वेतन तथा सुविधाएं अलग से पाते हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि आज विश्व विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई धीरे-धीरे खत्म हो रही है। इसलिए हमने यह चाहा है कि परीक्षा पूर्व कोचिंग सेन्टर से ऐसा कोई संस्थान अभिप्रेत है, जहां चिकित्सा या अभियांत्रिकी शिक्षा सहित किसी व्यावसायिक पाठयक्रम में प्रवेश के लिए अथवा नियोजन प्राप्त करने के प्रयोजन से किसी सरकारी अथवा निजी स्थापना द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए कोचिंग दी जाती है। यह स्थिति ऐसा गंभीर रूप धारण कर रही है कि जो हमारे नियमित विद्यालय हैं, उनमें पठन-पाठन का सिलसिला धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। यदि इस स्थिति को रोका नहीं गया तो मैं समझता हूं कि जो नियमित विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय हैं, अभियांत्रिक और चिकित्सकी महाविद्यालय हैं, उनकी हालत निरंतर खराब होती चली जाएगी। यदि आप चिकित्सीय प्रवेश देखें तो सरकारी महा विद्यालयों को छोड़ कर जो निजी संस्थान हैं यदि उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किसी को दाखिला लेना है तो आज की तारीख में डेढ-डेढ करोड तक केपिटेशन फीस हो गई है।

यदि आपको हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में दाखिला चाहिए, तो उसकी फीस सवा करोड़ रूपये हो गई है। एक करोड़ रुपये में तो जो दूसरे साधरण विषय हैं, उनमें दाखिला होता है

[श्री मोहन सिंह]

घाटे का सौदा यदि कहीं है, तो निजी तौर पर चलने वाले उद्योगों में है, लेकिन यह जो शिक्षा का उद्योग है, इसमें घाटे की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि बी.एड. के मान्यता प्राप्त विद्यालयों का ठीक से निरीक्षण किया जाए, तो रिश्वत दे कर बहुत बड़े पैमाने पर महाविद्यालय खुल गए हैं, जिनमें केवल बी.एड. की पढ़ाई दी जाती है। यदि आप गाजियाबाद और साहिबाबाद का निरीक्षण करें, तो जितनी पुरानी मिलें थीं, जब वे बन्द हो गईं, जर्जर हो गईं या बीमार पड़ गईं, तो उन्हीं उद्योगपतियों ने उनको रीमॉडल करके पांच-छः कमरे बना दिए और एन.सी.ई.आर.टी. को एक लम्बी रकम दे कर बी.एड. की मान्यता ले ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने बी.एड. के दाखिले के लिए 30,000 रुपये की फीस निर्धारित की। यदि आन उन महाविद्यालयों में जाएं, वहां पर न तो फैकल्टी है और न ही पढाई होती है। आप 30,000 रुपये की फीस जमा करिए और वह 30,000 रुपया इस बात के लिए जमा करिए कि आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। जब परीक्षा की तिथियां घोषित हो जाएं, उस समय आप परीक्षा देने के लिए आइए, तब 30,000 रुपया और जमा करिए और जितनी पाठ्य-पुस्तकें हैं, उनको कमरे में रुख कर अपनी परीक्षा दीजिए। यदि इस तरह का प्रशिक्षण और पढ़ाई बी.एड. में होगी, तो कैसे सुयोग्य अध्यापक रखे जा सकेंगे? ऐसे कैसे हम सुयोग्य डाक्टर पैदा कर सकते हैं? कैसे हम सुयोग्य इंजीनियर पैदा कर सकते हैं? हालत बड़ी खराब हो रही है। इसको काबू में रखने के लिए एक ऐसे बोर्ड की आवश्यकता है, जो इनकी फीस को भी निर्धारित करे और पठन-पाठन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी कड़ी नजर रखे। अमूमन आज हम देखते हैं कि जब कभी इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी या मैडिकल की परीक्षा होगी, तो उन सबके पेपर आउट मिलेंगे। यह कौन करता है? यह कोचिंग सैंटर चलाने वाले, जो कोचिंग सैंटर के इंतजामिया लोग होते हैं, वे ही इन पर्चो को किसी तरह मिल-जुल कर आउट करते हैं। यदि पर्चा आउट नहीं भी होता है, तो ये लोग एक झूठा पर्चा बाजार में फ्लोट कर देते हैं और हल्ला फैला देते हैं कि पर्चा आउट हो गया। ऐसे में परीक्षा रोक दी जाती है, कोई फर्जी आदमी पकड़ा जाता है और उसको सजा हो जाती है।

कुकुरमुत्ते की तरह चलने वाले जितने कोचिंग सेंटर्स है, अगर इनको नियमित नहीं किया गया, तो भारत में शिक्षा की हालत उत्तरोत्तर बिगड़ती जाएगी। आम लोगों को हम शिक्षा तो दे देंगे, लेकिन गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं दे पाएंगे, जिससे भारत के सही नागरिक पैदा हों, जिन नागरिकों के जरिए हिन्दुस्तान दुनिया में यह कह सके कि सबसे पढ़े-लिखे लोग भारत में ही होते हैं और इतने योग्यतम लोगों का देश दुनिया में भारत के अलावा कोई और नहीं है। धीरे-धीरे हमारी यह रैपुटेशन खत्म हो रही है।

आप विश्वविद्यालयों का परीक्षण यदि ठीक से लें तो इंटरमीडिएट पास करने के बाद सभी लड़के या तो इंजीनियर होना चाहते हैं या आई.आई.टी. में जाना चाहते हैं अथवा इसी तरह के किसी अन्य व्यावसायिक संस्थान में जाना चाहते हैं। धीरे-धीरे गणित और विज्ञान की पढ़ाई का विनाश हो रहा है। जो इस देश में तकनीकी और चिकित्सकीय ज्ञान का केन्द्र है, जिसे हम विज्ञान और गणित कहते हैं, इनकी पढ़ाई शून्य होती जा रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके जरिए हमारी मांग है कि भारत सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक सोचे और एक ऐसे प्राधिकरण की नियुक्ति करे, जो इन पर कड़ी नजर रखे और इनको ठीक से नियोजित करने का प्रयास करे, यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद।

The question was proposed

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Pre-Examination Coaching Centres Regulatory Authority Bill, 2010 moved by the senior Member, Shri Mohan Singh, is very much relevant because modern education is a very tough education today, which is based on very tough syllabus. At the time of admission of children in schools, the private schools are conducting interviews even though the Supreme Court has given a direction that there should not be any interview for LKG and UKG classes. But schools are conducting interviews at every stage. They ask for a detailed profile of every child, like what is his background; what is the education of his mother; what is the education of his father; how many brothers and sisters; how many family members, etc. They are asking these kinds of details. The present system of education is really very tough. You need technical assistance; you need scientific assistance; you need mathematical assistance. These are all things which are not available for poor families. They can learn only in classrooms where the teachers, in some way or the other, teach these poor people specifically. But most of the teachers do not find time to teach these students. We cannot blame them because they have to cater to 40 to 60 children in a classroom. Therefore, they are unable to do justice to these children. As a result, these children are having very low IQ. Within a period of 40 to 45 minutes, the child has to absorb the whole subject, which is taught by the teacher. That is a very tough job for a child. Then many of the families do not take proper care of their children. They are simply handing over their children to schools. They feel that it is sufficient for them and their duty is over. But the rich people or the people who can afford tuitions for their children, send their children for tuitions in every subject. In this way, many of the teachers are earning huge income by taking tuitions in same schools, same colleges and same educational institution. In this way, teachers are earning parallel income. So, they are least bothered about poor children who do not have access to coaching. But we are worried for children who do not have access to coaching; who do not have access to such opportunities to learn more for preparing for common examinations. Therefore, this is a very important issue because we all are saying that our modern education should be of international standard. At the same time, we have to see the real picture at the grassroots level also. Therefore, the Government is having an obligation to see that there are separate coaching centres to cater to the needs of children. In the USA, the system is such that community colleges are encouraged there. In the USA, there is no need for any basic education to join a community college. They can chose any field of their choice and get the training accordingly. The community colleges assist them, give them training and then give a certificate also which is acceptable for any job. They do not bother about educational background. They are particular about skill; they just try to find out whether that particular person has got a skill to do a particular job for which he is being selected. Therefore, we have to look into this aspect. Our country is not

3.00 P.M.

[Dr. E.M. Sudharsana Natchippan]

having the luxury of going to schools; our country is having the necessity of going to schools. If one is not educated; if one does not have any certificate, even a bride refuses to marry him. Therefore, the State Governments should come forward with some packages in order to give coaching to children in evening hours. For example, we are doing it in Tamil Nadu. The Tamil Nadu Government has allowed special coaching classes in every Government school, wherever possible. In rural schools, the headmasters, the teachers who are interested in getting better results for their school, so that they can attract more students, encourage the children by having evening tuitions and early morning tuitions. In some cases, they ask the children to sit in the classrooms throughout the night so that they can give them coaching to get them prepared for the next day. And they will be able to come up with perfection. When there is absence of help from the family, then, there should be some help from the Government. That is the necessity now. We are giving noon meal; no doubt, it is very important. The late Shri Kamaraj, as Chief Minister, introduced it in Tamil Nadu. Now because of the efforts of Madam Sonia Gandhi, it has come up throughout the country. Nearly twelve crores of students are taking their meals under the Mid Day Meal Scheme. Similarly, if we want to have human resources, better skill, better education, I feel that the Government of India should also participate in it. If the State Governments are not coming forward, and if we cannot afford to give money for such coaching, then, we are depriving the real people, who are otherwise now accommodated by way of the Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme. The family is now allowed the facility of creches. The family is allowed to have their income to be saved. The family is allowed to have insurance benefits. The Government of India has provided them all these facilities. The Government of India is providing their children Mid Day Meal. The Government of India is providing them Sarva Shikhsa Abhiyan, where schools with good laboratories and play things are provided. Building roads to those schools and building of separate toilets for boys and girls are all being taken up by the Government of India. We are giving textbooks and bags to children. We are even giving them bicycles under the Sarva Shiksha Abhiyan. Then, why can't we give them this coaching as well? I feel that the Sarva Shiksha Abhiyan should have a small component for this also. So, wherever there is a need for that, the scope should be enlarged. That is an important thing because the working hours of the rural poor are totally different from the others. They have to work throughout the day. There is no fixed time of eight hours of duty for men and women there. Wherever opportunities are there, they have to go for work, earn money and look after their families. In fact, we are giving children free uniforms. We are giving educational tools to them. In Tamil Nadu, we are even providing free laptops for

children studying in +2 and colleges. This way, every State Government should get the awareness and see to it that ordinary students are given access to all the modern tools which are available for a rich student. Sir, you know very well, when Shri M.G. Ramachandran was the Chief Minister, he even provided tooth powder for children. He provided them with chappals. That was the attitude of the Tamil Nadu Governments. Sir, especially, in North India, there is a huge human resource available, and people are migrating for want of some jobs. That is the state of affairs of several countries through out the world. But, in India, we are having the potentiality now. Through Sarva Shiksha Abhiyan and other schemes, we are getting the skilled people, the largest number at every stage. Whether it is below 30 years or above 30 years or above 50 years, we are having a huge level of human resources available. But what about the children who are growing up now? They have to be provided with all the facilities. If we are doing it, then, we are really helping people at the grass root level to come up to the desired standard and participate in nation-building. They will have the knowledge to understand the world. Our educational system is, basically, oriented towards that. All the subjects, whether it is science, economics or history or even languages, including regional languages, are all based upon teaching children how to live in the society, how to understand the society around us, how to understand the environment around us, how to live in this huge population. These are all put up as lessons in the syllabus. Therefore, if they understand this properly, instead of merely getting good marks or getting certificates or simply learning to read and write and enhancing the memory power, if they understand the need of the society and the need of the environment, then, such children will become good citizens as well. Even a well-educated person, a person with a Masters Degree or a person who is a Ph.D. holder, is joining the terrorist movement because they have not understood education properly. They have got a deep hatred for the society.

They cannot brave the pressure groups which are around them. They cannot understand why they are not getting accessibility. Whether they are from the Scheduled Castes or from the Scheduled Tribes or minorities, they cannot understand how to live within the society because the education system is there but they cannot realise the education system. Therefore, they are feeling that if education is only to get employment and if they get marks, even then they cannot get a proper position in the world, in the society. Therefore, they hate the society and they have gone in the trap of terrorist movement. Therefore, to stop that in the tribal areas, we have to help the Scheduled Caste people's habitation, minority people's habitation, by way of coaching centres. In two ways we are helping them; one is to understand the environment and live with the society, and show their productivity, show their activity and show their ability for living with the society

[Dr. E.M. Sudharsana Natchippan]

and another way is, we are asking them is to come up to the standard with other rich people who are competing at the national or State level General Education and Examinations. The General Education and Examination is a very tough job for anybody nowadays. When they come to the eighth standard or tenth standard or twelfth standard, they have to compete. Many of the parents are spending huge amounts of money for their children because they feel that if they get through their twelfth standard by merit, they can get admission in the medical college, they can get into an engineering college; they can get into IT; they can get into foreign education. Therefore, they are spending huge money for that. What about the persons who are not having money? What about the persons who have got no accessibility of getting much more knowledge rather than what is available in the classroom within a confined time? The teacher cannot have the time to discuss with them, and find out and clarify their doubts. They are rushing through because the number in every classroom is gradually increasing. Every private school is coming forward to have more commercialisation rather than more socialisation or more culturalisation. Therefore, when it is commercialisation and financial aspect, people are thinking about. This Bill, really, I feel, will give a new focus to the Government to come out with a better enactment and to also initiate a process. Finally, I would like to submit that every State Government is giving some help to the school children and college studying students only by giving Government orders because by an executive order it can remain, it can continue or it can be reduced. Madam Sonia^ Gandhi brought the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme because it should be a statutory right. If a statutory right is violated, if it is not given, then they have got the right to agitate against it. Therefore, this type of coaching centre right should also be enacted and if the Bill is passed at the national level with the allotment of certain money for that purpose, I hope the State Governments will also accept it because we know very well, the State Governments are very much nearer to the people. They want to play the game according to the people's fancy, but we are sitting at the national level where we are looking at competition at the international level. Therefore, we have to bring our human resources to the skilled people and meritorious people so that many of the people can come up. I can cite the example of Dr. Abdul Kalam who studied when Kamarajji was Chief Minister. We called it an ordinary board school at that time in Rameshwaram. It was a small hamlet at that time. But he has become the topmost man in India. Similar is the case with Chandrasekhar. We can say that he is the top-most man who got the Nobel Prize. Many of the Nobel Prizes were won by the Tamil Nadu scientists because they got education at the earlier point of time. Even IAS officers, engineers and many of the people have come up in Tamil Nadu and Kerala

because of education. Therefore, this is a very good focus on which our senior Member Mohan Singhji has introduced this Bill, and, I support the intention of bringing the Bill, but the Government can appreciate it and they can come forward with a new proposal for this purpose. Thank you.

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): धन्यवाद, सर। सबसे पहले मैं मोहन सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उस एक समस्या को लेकर आज पार्लियामेंट में यह प्राइवेट मेम्बर्स बिल पेश किया है। मैं आशा करता हूं कि आज जो यहां डिस्कशन होगी या सजेशन आएंगे, उसके मद्देनजर सरकार कोई कानून लाएगी।

फील्ड में घूमते हुए जो कुछ व्यक्तिगत एक्सपीरिएंस हुए हैं, उनको भी मैं हाउस में शेयर करना चाहता हूं। आज देखा गया है कि जिस टीचर की गांव में पोस्टिंग हो जाती है वह अपनी तनख्वाह तो पूरी लेता है, लेकिन कभी वहां पढ़ाने नहीं जाता और वह अपने स्थान पर किसी कोई लोकल आदमी को अपनी सेलेरी में से दो हजार, तीन हजार देकर वहां रख देता है। वह खुद महीने के अन्त में अपनी सेलेरी लेने आता है। इस प्रकार वहां अनट्रेंड टीचर बच्चों को पढाता रहता है। यह एक बहुत बडी समस्या देश में है, इसको रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। दूसरी बात, कोचिंग तो मुझे दिल्ली में लेनी है और एडमिशन गांव मे लेना है, ताकि गांव मे मेरी हाजरी लगती रहे और मैं दिल्ली में बैठकर कोचिंग लेता रहूं। तो ऐसे भी अनेक केसेज हैं जिनके कारण विद्यार्थी लाखों रुपए देकर कोचिंग लेते हैं। गांव के स्कूल के रजिस्टर में आता है कि इतने विद्यार्थी यहां पढ़ते हैं और यह-यह चाहिए। लेकिन इनफेक्ट वे बच्चे कहीं न कहीं यहां कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेते हैं। मैं भी प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। उस समय हमारे पास बैठने के लिए न बैंच होती थी और न डेस्क होती थी। हम अपने घर से ही बैग लेकर, बोरी लेकर जाते थे और वहां पढ़ते थे। उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल में दसवीं की और फिर हम एक कॉलेज में गए । प्राइमरी एजुकेशन एक गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी दी जा सकती है, क्योंकि वहां पर ट्रेंड टीचर और सरकार की चिंता उसके पीछे होती है। लेकिन यहां जो एक कमी रहती है कि वहां का टीचर अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़ाकर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। उससे जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनके मन में यह शंका रहती है कि यहां पर एजुकेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि यहां टीचर का बच्चा नहीं पढ़ता, वह किसी और स्कूल में जाता है। इस कारण यहां के बच्चों के मन में इम्प्रेशन ठीक नहीं पड़ता है।

मैं सदन के सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बच्चों की psyche भी कैसी हो गई है। मेरा एक दोस्त है उसकी बेटी एक ए.सी. स्कूल में पढ़ती है। उसने बताया कि स्कूल से घर लौटते समय जब 15 मिनट का रास्ता शेष रह जाता है तो उसका फोन आता है कि मम्मा, ए.सी. ऑन कर दो, मैं पहुंचने वाली हूं। तो घर में ए.सी. ऑन हो जाता है और वह घर में ए.सी. रुम में आ जाती है। एक दिन उस बच्ची ने शरारत की तो उसकी मां ने कहा कि अगर तूने पढ़ाई ठीक नहीं की तो मैं तुझे एक नॉन ए.सी. स्कूल में करा दूंगी। तो उस बच्ची ने हैरान होकर पूछा कि मम्मा, क्या नॉन ए.सी. स्कूल भी होते हैं? इस प्रकार हमारे देश के बच्चों को इसकी भी जानकारी नहीं है कि किन परिस्थितियों में हमारे देश के गरीब बच्चे पढ़ते हैं। यह एक बहुत बडा गैप है। तो इसको कम करने के लिए, ठीक है, सरकार की चिंता है, एस.एस.ए. के कारण बहुत काम हुए हैं, टीचर्स प्रोवाइड हुए हैं।

[श्री अविनाश राय खन्ना]

तो मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहता हूं, जो मैंने कुछ किया है, वह भी इस प्लेट फार्म पर शेयर करना चाहता हूं। मैंने एक एन.जी.ओ. बनाकर चार गवर्नमेंट स्कूलों को एडॉप्ट किया। जब मैंने एडॉप्ट किया तो वहां का रिजल्ट जीरो परसेंट था, दो बच्चे पास्ड विद कम्पार्टमेंट, तीन बच्चे पास्ड विद कम्पार्टमेंट। उसमें 250-300 के करीब बच्चों की संख्या रहती थी। जो सबसे गरीब हैं और जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलती वे गवर्नमेंट स्कूल में आते थे। आज छठा वर्ष है, जब से मैंने उन स्कूलों को एडॉप्ट किया है, आज उन स्कूलों का हंड्रेड परसेंट रिजल्ट है और 1100 से 1200 तक एडमिशन उन गवर्नमेंट स्कूलों में हो गई है। मुझे एक दिन खुशी हुई कि जब मुझे किसी का टेलीफोन आया कि खन्ना साहब, मुझे अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना है, लेकिन एडमिशन नहीं मिलता है। तो मैंने हैरान होकर पूछा कि आप गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हो या किसी प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं। अगर हम थोड़ी सी भी चिंता करेंगे तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जहां ट्रेंड टीचर्स हैं वहां का बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है।

अब बात कोचिंग सेंटर की आती है। देखिए, आज एजुकेशन में बहुत ज्यादा कम्पटीशन है। हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन ले। तो वह फिजिक्स की भी ट्यूशन रखता है, वह केमिस्ट्री की भी ट्यूशन रखता है, वह मैथ्स की भी ट्यूशन रखता है और वह इंगलिश की भी ट्यूशन रखता है। इससे कितना बर्डन बच्चों के ऊपर पड़ता है। हमारे यहां ऐसे भी बहुत टीचर हैं जो अपने स्कूल में कम पढ़ाते हैं, लेकिन ट्यूशन में ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसी टीचर्स के बारे में भी बच्चों के अंदर ऐसी भावना पैदा हो जाती है और एसी बातें एजुकेशन के स्तर को बहुत नीचे लेकर जा रही हैं।

जो भारत की शिक्षा है, कहा भी गया है कि शिक्षा एक बहुत बडा दान है तथा वह दान के रूप में दी जाती थी। अगर द्रोणाचार्य की बात कहें तो एकलव्य के नाम से बस समझ ा में आ जाता है। एकलव्य ने सिर्फ द्राणचार्य की फोटो देखकर सब कुछ सीख लिया। सो हमारे यहां विद्यार्थियों की कमी नहीं है, बात यहां सिर्फ उनको ट्रेनिंग देने की है। मैं एक साल ह्यूमन राइट्स कमीशन में रहा हूं। मैं वहां का एक तजुर्बा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि सरकार Institute में भी किस तरह से धोखा होता है। एक फार्मेसी के स्कूल को दिल्ली की ए.आई.सी.टी.ई. से permission लेनी थी जोकि उस गवर्नमेंट स्कूल में नहीं थी। वह स्कूल चल रहा था और उसमें बी.फ़ार्मेसी का कोर्स हो रहा था। हम जब उस complaiant को consider कर रहे थे, तो उस डिपार्टमेंट से पूछा गया कि आपने permission क्यों नहीं ली? उन्होंने कहा कि permission लेने के लिए हमें क्वालीफाइड टीचर्स चाहिए और वे तब मिलेंगे जब उनको इतनी पे दें और हमारी पे गवर्नमेंट के पैरामीटर्स में आती नहीं है। हम तो बस इतनी पे दे सकते हैं। Ultimately Commission ने ऑर्डर किया कि इस स्कूल को बंद किया जाए और वह स्कूल बंद हुआ। आप या तो permission लो या वहीं टीचर्स प्रोवाइड करो। अब आप देखए कि प्राइवेट स्कूल्स कैसे permission लेते हैं? वे अपना बहुत बड़ा infrastructure बनाकर, लैब्स बनाकर खड़ी कर देते हैं और वहां जिस दिन inspection होती है, वह किसी टीचर को hire करके उस दिन उसकी हाजिरी शो कर देते हैं कि यह हमारे यहां टीचर appointed है। उस दिन Inspection report में आ जाता है कि यहां पर Rules and

Regulations के मुताबिक सब facilities provided हैं और इस स्कूल को permission देनी चाहिए। फिर जब Inspection team बाहर जाती है तो वह टीचर अपनी Parent Institution चला जाता है। यह भी एक तरह से Eye wash है। इसलिए जितने भी कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, वे एक व्यवसाय न बनें, वे बच्चों को ठीक तरह से एजुकेशन दें, यह बहुत जरूरी है। आज हो क्या रहा है? Suppose एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है। उसे उसी टीचर द्वारा लिखी किताब को खरीदना होता है क्योंकि उस टीचर की जितनी किताबें ज्यादा बिकेंगी, उसको उतनी ज्यादा royalty भी मिलेगी। इस ढंग से एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह से यूज किया जा रहा है।

अभी मैं जम्मू-कश्मीर की एक न्यूज पढ़ रहा था जहां कि एक स्कूल में एक बच्चा है व 16 टीचर्स हैं और वह बच्चा भी फेल हो गया। आप देखिए कि हमारी एजुकेशन का कितना बुरा हाल है। मैंने यहां पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन दिया था कि यूनिवर्सिटीज में वर्ल्ड में हमारी कितनी ranking है? सर, बडे अफसोस की बात है कि पहले सौ नंबर्स में भी हमारी किसी यूनिवर्सिटी की ranking नहीं है।

आप ट्रेनिंग सेंटर्स में admission की काफी भाग-दौड़ है। मैं कोटा जाऊंगा, मैं चंड़ीगढ़ जाऊंगा, अगर वहां सीट्स फुल हैं, तो उन्होंने एक Simple formula निकाल लिया है। ठीक है, आपको पंजाब से हरियाणा से कोटा आने की जरूरत नहीं है। हमने सेटेलाइट के थ्रू सारा सिस्टम तैयार कर लिया है, हमारी franchise फलां आदमी के पास है, आप पंजाब में बैठकर admission ले सकते हैं अगर मैंने क्वेश्चन पूछना होगा तो उसके लिए एक दिन निश्चित है, हम आपको उस दिन क्वेश्चन पूछने का मौका देंगे। अब आप देखें कि इतनी भारी-भरकम फीस बच्चे कहा से पे करेंगे, parents कब तक उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए कब तक इनके पीछे भागें और कहां से इतना पैसा लाएं? फिर इन सेंटर्स की क्वालिटी पर कौन ध्यान देगा? कोचिंग सेंटर्स में क्या चाहिए? मैने तीन ऐसे टीचर्स देखे हैं जिन्होने government job से resign करके एक कोंचिंग सेंटर खोल लिया और वहां इतना rush है कि उनको बच्चों को पढाने के लिए टाइम नहीं है। इसका कारण यह था कि वे कॉलेज में पढ़ाते नहीं थे, अपना कोंचिंग सेंटर खोल लिया। अब चूंकि वे Expert teacher हैं, उनके लिंक्स ऐसे हैं कि उनको मालूम है कि कहां से पेपर सेट होना है और कहां valuation के लिए जाना है। वहां तक फॉलो करने के charges भी बच्चों से लिए जाते हैं। तो क्या यह जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, बिजनेसमैन, Polticians इन सबको पैदा करना है, वहां की एजुकेशन क्या सरकार के संविधान व कानून द्वारा तय parametes के हिसाब से दी जा रही हैं या नहीं? इन कोंचिग सेंटर्स का स्टे़डर्ड क्या है? क्या वहां बच्चों को पढ़ने के लिए पूरी सुविधा है? क्या वहां कोई Rules and regulations हैं? Admission के लिए जितने parameters चाहिए, उसके मुताबिक वहां टीचर्स हैं या नहीं हैं?

मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर एक रेहडी वाले ने कहीं किसी शहर में या गांव में रेहड़ी लगानी हो, तो उसको वहां की म्युनिसपेलिटी या बी.डी.ओ. से परमिशन लेनी पड़ती है कि मुझे यहां पर सब्जी बेचने के लिए रेहडी लगानी है। क्या सरकार के कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि किसी ने अगर कहीं कोचिंग सेंटर खोलना है तो उसके लिए उसे सरकार से परमिशन लेनी होगी? क्या सरकार की तरफ से कभी उस इंस्टीट्यूट का कोई इंस्पेक्शन किसी डी.ई.ओ., डी.सी. या एस.डी.एम. द्वारा किया जाता है? मेरा

[श्री अविनाश राय खन्ना]

ख्याल है कि ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई रूल-रेगुलेशन नहीं है। जिसका मन चाहे, घर में बैठ कर अपना एक ट्यूशन सेंटर खोल ले, जिसमें बच्चे आना शुरू होंगे, वह पढाना शुरू करेगा और इस तरह उसका एक प्रोफेशन बन जाएगा। आज लोगों के मन में यह एक बडा प्रेसर है, क्योंकि अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग होगी कि फलां स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन लेना है तो आपसे कौन से क्वेश्चन्स पूछे जाएंगे, इसके लिए आप एडमिशन ट्रेनिंग लीजिए और चूंकि बच्चे ने एडमिशन लेना है तो उससे भी कौन-कौन से क्वेश्चन्स पूछे जाएंगे, इसकी भी ट्रेनिंग देंगे। यह पूरा एक ऐसा बिजनेस बन चुका है, जिसे रेगुलेट करने के लिए मोहन सिंह जी ने आज यहां अपनी वेदना, अपने मन की बात रखी है, जिसे ध्यान से अगर हम देखें तो लगता है कि आज यह समय की मांग है।

महोदय, यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं, चूंकि मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, कि विदेश जाने का ट्रेंड बहुत हो चुका है और विदेश जाने के लिए आपको वहां की लैंग्वेज सीखनी होती है। आईलिट के नाम से आज इतनी दुकानदारी चल रही है कि आज छोटे-छोटे गांवों में भी आईलिट ट्रेंनिग सेंटर खुल चुके हैं। बच्चे ने कितने पाइंट में पास होना है, वह सब उसमें बताएंगे। आईलिट करने के लिए वहां पर जो क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशन हो कि जब बच्चा इंटरव्यू के लिए जाए तो वह पास हो जाए, वह है या नहीं है, इसको कौन डिसाइड करेगा? ऐसा देखा है कि अगर उसका आईलिट का काम नहीं चला और जब उसने देखा कि मैने दो-तीन लोगों को विदेश भेज दिया है तो वह अपना यह काम छोड़ कर लोगों को विदेश भेजने का काम शुरू कर देता है। यह एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप मे फैल रहा है, इसको हमें रोकना पड़ेगा।

यहां जो छोटी-छोटी बातें आ रही है, उनकी ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं ली, जो सिर्फ स्कूल में पढ़े हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें कोई एग्जाम देना है तो पहले तो बहुत से बच्चों को यही पता नहीं चलता कि कब उसके टेस्ट का निकलेगा, कहां से फार्म मिलेगा और वह फार्म कहां जमा कराना होगा। एक इंस्टीट्यूट में मुझे जाने का मौका मिला। वहां मुझे बताया गया कि देखिए, बायोडाटा कैसे तैयार करना है, उसके लिए भी हमने एक सैल बना रखा है, क्योंकि जितना इम्प्रेसिव बायोडाटा होगा कंपनी उसको उस ढंग से लेगी। एक गरीब बच्चा, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसको ऐसी फेसिलिटी कब मिलेगी? इसलिए मै चाहूंगा कि मोहन सिंह जी यह एक बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं, सरकार को सीरियसली इसे देखना होगा। जो प्रेक्टिकल प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, देश मे देख रहे हैं, उसके लिए बच्चों के साथ इंटरएक्शन करके, पैरेंटस के साथ इंटरएक्शन करके एक ऐसा कानून लाया जाए, जिससे देखा जा सके कि जहां कोचिग एग्जामिनेशन के लिए हो रही है, वहां पर क्या किसी लॉ को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्या वाकई वहां जो कोचिंग दी जा रही है वह अपटू मार्क है या नहीं और क्या उनकी कोई चैकिंग हो रही है या नहीं हो रही है? इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि सरकार कुछ कोशिश करे और एक ऐसा कानून बनाए।

अंत में मैं इस बिल को अपनी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन देता हूं और मोहन सिंह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

DR. JANARDHAN WAGHMARE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to speak on this Bill. We are discussing a very important Bill, and the problem is really very serious. We have to find out what are the reasons of the mushroom growth of coaching classes. You find thousands of coaching classes everywhere in small towns and even in villages also. What is the reason? Why students go to coaching classes? The main reason is, proper and effective teaching does not take place in schools and colleges. This is the main reason. The teachers and lecturers who are teaching in their own institutions are not very serious about their profession. Effective teaching—this is my experience also—does not take place in schools and colleges.

Secondly, who are the people who run these coaching classes? Teachers themselves, those who are teaching in colleges and schools, they run the classes. There are many others but they are involved in coaching classes. This has to be banned really. They, of course, ask the students to join their own classes especially in colleges. Coaching classes run for Xth Class, science stream, Xlth and XIIth. These are the examinations which are career-making examinations. That is why there is a rush. This is the reason why there is this mushrooming growth. So, these teachers should be prevented from this. There should be some accountability on the part of the teachers that they will not teach in coaching classes, they will teach only in their own schools and colleges, So, this condition has to be laid down. They are earning fat salaries and yet they run coaching classes and get more money. This is the reason. Secondly, if you go deeper into the problem, our whole education system has become examination-oriented, only examination. You, of course, get the guides, a lot of copying takes place in the examinations, by hook or crook you get through the examination. So, this has to be taken into consideration. Our education system is not knowledge-oriented, it is examination-oriented. That *is* why there are coaching classes. There is *one* more reason to this, in our schools we have not decided teacher-students ratio. In a particular class, you may find 100 students, 150 students, even 200 students. A teacher teaching that class cannot give justice to them. He cannot give individual attention to every student, He cannot, give homework. He cannot, of course, take their problems, educational problems especially, into consideration. That is why this type of mass education where education does not take place has to be given a thought. There should be some reformation. We need radical reformation in examination system; we need radical reorientation of the whole examination system. There should be some ratio of teachers and students and then alone teachers can deliver. Of course, money-oriented approach is there. Apart from this, these are some of the reasons. Therefore, this has to be curbed. You cannot stop coaching classes, they have to be regulated and some kind of accountability has to be fixed. There should be some

[Dr. Janardhan Waghmare]

permission on the part of the people who run coaching classes. That is how you have to do these things. Mathematics, English, science, commerce accountancy, etc. are some of the subjects where students rush for coaching classes. So, the whole approach has to be changed. Rote is very common in our examinations. So, we have to make efforts. It is very difficult to do that reformation. But, anyway, our education system should be knowledge-oriented and not examination-oriented. In the past the UGC had given a recommendation that there should be delinking between higher education and degree. One should not teach only for job. Therefore, we should acquire knowledge but we could not succeed in that also. Examinations will be there but the mode of examination has to be changed and emphasis on examination alone has to be shifted elsewhere.

[THE VICE CHAIRMEN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN) in the Chair

These are some of the reasons. In our education system, since it is examination-oriented, a lot of copying takes places.

So, that has to be curbed. Even people who are there to prevent copying they themselves become means of providing copying, even policemen, we have seen. The whole thing has become really very complex, very perplexing. So, this has to be looked into very radically. And, some change in the whole approach has to be there. So, what I feel is that there should be a comprehensive legislation for this. Responsibility of teachers, responsibility of the parents and the responsibility of the managements has to be fixed. There should be a very, very comprehensive legislation. We should fix accountability, responsibilities, their duties, etc. Then alone, you can succeed in this.

Thank you very much, Sir

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Andhra Pradesh): With gratitude to the Chair, I rise to present myself. This is my fourth day, after taking oath as a Member of Parliament, in this red-coloured House, the House of Lords. First of all, I would like to place my gratitude on record that me, Congress *aam aadmi*, could reach this highest House of Indian Parliament with the grace and magnanimity of my leader, the President of the Indian National Congress, Shrimati Sonia Gandhiji. Her selection with the input of national leadership and my State leadership of Andhra Pradesh enabled a person like me, who never filed a nomination paper to face any election, just being an organization person, to reach this House so as to convey the beauty and scope of Indian democracy. Friday, a Private Members' Day, is a sort of free-will day. And, today I have been given a chance to speak here. I shall try to make out and present my beginning words. Shri Mohan Singhji, as I understand, is

a senior Member of this House. He is having a lot of concern towards the societal responsibility to improve the needs of education. I also heard the views of other hon. Members, including senior educationist Dr. Janardhan Waghmare. I shall recollect that I am a person from rural India, In 1976, I had travelled to New Delhi to represent in the three-day United Schools Organization Convention, At that time, I was given an opportunity to participate in the English declamation context. And, the topic was If I were the Education Minister of India—what reforms I would bring', I was studying in my mother tongue, Telugu. The teaching faculties can very well understand how the rural India was. But the fact that despite being from the rural background I could participate at the national level in the United Schools Organization Convention, proves that there is no necessity of any coaching. This also proves that there is no necessity of prompting a child. The only necessity is that there should be a holistic approach and create a conducive environment for the children to attain and sharpen their menial faculties.

There is a need to create a necessary holistic approach, and to also create a congenial environment for the children, so that they could attain or search over their inculcative faculties. How we are going ahead should be, time and again, verified. In my State, Andhra Pradesh, mushrooming of engineering colleges has delinked the necessity of coaching centres. Now, straightaway, the children who have completed their Intermediate, with their marks and their attempt in single go, could get specialisation faculty of their choice. If they do not get the institute of their choice, they could join other institutions that are there. As it is, if for a small family dispute, we go for a counsel, it would, unnecessarily enlarge the complications. Same is the case here. Unnecessarily, if the children are prompted to join coaching centres, their learning skills and their own self-searching faculties will not flourish. For this, congenial environment, unit-wise, school-wise, college-wise and engineering college-wise, needs to be created. Then, there will not be any necessity of support for them to face Group I or Group II Civil Services exam. Even then, these days, we are hearing and facing the pressure of joining the coaching centres. Though I understand, and you all understand, with the technological advancement and with the web-based society, knowledge availability has become easy. For a child who is prepared to enhance his understanding level, he or she could, certainly, get himself or herself tested any time, and they could have various module tests with those things. To my understanding, now, in my State, and also in several other places, gradually, children are getting accustomed to face the test on computer. Even then, the issue of mushrooming educational institutions and re-prompting mechanisms called 'coaching centres has to be seriously looked into. The concept of Mohan Singh ji is based on the need to understand the examination process into which the students are being sent into. For that, there is a necessity to understand the holistic

[Shri Ananda Bhaskar Rapolu]

pattern of learning. Once the coaching centres get dispassioned, once the parents understand seriously that sending their child to a coaching centre is not a fashion symbol or a status symbol, only then, will this situation alter. Meanwhile, a sort of intervention from the Government side will also be appreciated. With that, the purpose of spreading education in a holistic manner and creating a proper environment for each and every student could be attained. For this, the concept or the approach or the thinking of Mohan Singhji could be understood. I request the Government of India, the Ministry of Human Resource Development, to take this opportunity to delve into the subject seriously and come out with a proper mechanism of enactment to curtail unnecessary brain-washing of the children so that they could learn on their own. Thank you very much.

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मोहन सिंह जी के प्रति उन तमाम अभिभावकों और बच्चों की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा कि कोंचिंग क्लासेज के नाम पर शिक्षा के आलय नहीं, शिक्षा के जो कत्लखाने चल रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने जागरुकता और चैतन्य जागृत कर पूरे देश को उपकृत किया है।

महोदय, यह जो विधेयक है, यह द्रोणाचार्यों द्वारा अमीर और राजसी ठाठ-बाट में रहने वाले अर्जुनों के लिए एकलव्य के अंगूठे काटे जाने की प्रक्रिया को रोकने का कानून होगा। इस देश में शिक्षा को कभी भी व्यापार और धनी लोगों की तिजारियों में बंद नहीं किया गया। यह वह देश है, जहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए और गुरूकुलों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोरिया, जापान, चीन और सम्पूर्ण पूर्वी एशिया से लोग आते थे और जहां कहा गया,

एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन:।।
स्वम् स्वम् चरित्रम् शिक्षेरण पृथिव्याम् सर्व मानव:।।

इस देश में, विश्व के कोने-कोने से लोग आकर, पास में एक दमड़ी न रखते हुए आचार्यों की शरण मे विश्व की श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त करते थे। यहां के ऋषियों, यहां के गणितिज्ञों, यहां के रसायन शास्त्रियों और भौतिक शास्त्रियों ने पृथ्वी की गति मापी, प्रकाश की गति मापी, रसायन शास्त्र दिया, कभी जंग न लगने वाला लोहा दिया, उन्होंनें दशमलव प्रणाली दी, उन्होने शून्य दिया, उन्होंनें अंकगणित दिया, उन्होंनें एक हजार वर्ष पहले घोषित किया कि एक सूर्य नहीं, अनेक सूर्य होते हैं, जिनको आज के वैज्ञनिक सिद्ध कर रहे हैं। इस देश में जो नियमित विद्यालय और संस्थान हैं, वहां पर शिक्षा को पूरी तरह से समाप्त किए जाने के लिए विद्यालयों की बगल में ही जो कोचिंग सेंटर्स खुलते हैं, जहां वह वहीं व्यक्ति, जो विद्यालय से वेतन प्राप्त करता है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए टीचर रखा जाता है और जिसे आज बहुत अच्छा वेतना मिलता है, उसे 40000 रुपये से लेकर 90000 रुपये तक वेतन मिलता है, वह विद्यालय की शिक्षा को छोड़कर अपने घर में कोचिंग सेंटर चलाता है या किसी दूसरे कोचिंग सेंटर में एक लाख, दो लाख रुपये प्रति माह के वेतन पर शिक्षा का कारखाना, शिखा की फैक्ट्री चलाता है, जहां पर फास्ट फूड की तरह से पैसा देकर डिग्री खरीदी जाती है। वे लोग शिक्षा के साथ और अपने छात्रों के साथ ईमानदारी नहीं रखते हैं, वे विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। वे किसी भी बच्चे को देखकर पीरिएड के बाद में कहते हैं कि तुम शाम को आ जाना, तुम्हें अच्छी कोचिंग क्लास में ले जायेंगे। तुम्हारी जो पढाई की तमाम

कमजोरी है, वह दूर कर दी जाएगी। जब वे अपने विद्यालय में अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी नहीं रखते हैं, तो वे किस प्रकार के विद्यार्थियों का निर्माण कर रहे होंगे, वे किस प्रकार के आचार्य होंगे।

महोदय, इस कारण से इन संस्थानों में गुरू के प्रति श्रद्धा समाप्त होती गई है, आचार्यों के प्रति सम्मान घटता गया है। हमारे एक मित्र अच्छे कहानीकार हैं। उन्होंने एक कथा लिखी कि एक कालेज में एक लड़का सिगरेट पी रहा था। उसने सामने से देखा कि प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। उसने झट से सिगरेट पीछे दबा ली। उसके दोस्त ने कहा, अच्छा बडी इज्जत करता है, डर के मारे सिगरेट छिपा ली। उसने कहा नहीं यार, अगर आता तो मुझसे सिगरेट मांग लेता, इसलिए पीछे कर ली। यह हमारे विद्यालयों का हाल हो गया है। ऐसे विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि डिग्री खरीदने की फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं।

महोदय, मैं उत्तराखंड प्रांत से आता हूं। वहां दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विद्यालय माने जाते हैं।

सबसे मंहगे विद्यालय भी उत्तराखंड में हैं। वहां पर एक-एक विद्यालय ऐसा है, जिसमें एक बच्चे की वार्षिक फीस सात लाख रुपए से लकर आठ लाख रुपए तक लगती है। ये वे विद्यालय हैं, जिनमें दुनिया भर के छात्रों को इकटठा करते हैं और उनके मां-बाप से फीस लेते हैं तथा शेष खर्चे अलग से लिए जाते हैं। मैं यह बात वहां जाकर भी कहता हूं कि आप डिग्री और सर्टिफिकेट देने की फैक्ट्रियां चला रहे हैं। मैं यहां किसी भी विद्यालय का नाम नहीं ले रहा हूं। उन विद्यालयों में एक भी ऐसा नहीं है कि जिनमें पढ़ने वाले बच्चों ने वहां की हवा, पानी और संस्कृति तथा वहां की जमीन पर रहकर विद्या ग्रहण की हो। उन बच्चों को न उत्तराखंड की शिक्षा का ज्ञान है और न ही गंगा, यमुना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमालय और ऋषिकेश का ज्ञान है। जिन लोगों ने Victoria cross से लेकर परमवीर चक्र तक जीते हैं, उनके बारे में बच्चों को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। वे लोग देश को और जमीन को एक प्लेटफार्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देंगे।

महोदय, सुबह सात बजे से लेकर दो बजे तक बच्चा स्कूल में रहता है और ढाई-तीन बजे घर लौटता है। उसके तुरत बाद उसको home work करना पड़ता है या अगले दिन की तैयारी करनी पड़ती है। हम बच्चे से यह अपेक्षा करते हैं कि वह extra-curricular activities में हिस्सा ले, वह अपने व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए काम करे, declamation contest में जाए, भाषण प्रतियोगिताओं में जाए, खेल में जाए, गीत और संगीत में रुचि ले तथा केवल किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहे, लेकिन उसके पास तो समय ही नहीं होता है। कक्षा आठवीं, नौवीं, दसवीं और बारहवीं की एक-एक पुस्तक बारह सौ, पन्द्रह सौ पृष्ठों की होती है। जो उनकी guide books होती हैं, वे दो-दो किलो की होती है और चार-चार हजार में मिलती है। जब मैं स्वयं अपने बच्चों की पुस्तकों को देखता हूं, तो मै स्तब्ध रह जाता हूं कि कोई बच्चा इन पुस्तकों का पढ़कर कैसे आत्मसात करेगा और उसके आधार पर कैसे परीक्षा देगा? आज का समय इतना Competitive हो गया है कि सौ प्रतिशत अंक लाने पर भी प्रवेश नहीं मिलता है। यदि बच्चा 90 प्रतिशत अंक नें आए तब भी वह मायूस हो जाता है कि उसके 95 प्रतिशत अंक क्यों नहीं आए, उसको अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पाएगां। यह परिस्थिति आज शिक्षा की बोझ बन गई है और जिसके कारण वे कोचिंग क्लासेज एक escape route की तरह से निकले, एक आसान रास्ता निकले कि हम तुम्हें वह जादुई छड़ी दे देंगे

[श्री तरुण विजय]

कि तुम्हें स्कूलों की पुस्तकें न पढ़नी पड़े। स्कूलों में अगर तुम्हें अध्यापक नही पढ़ाते हैं तब भी तुम चिंता मत करो और हम तुम्हें एक छोटा short-cut दे देंगे। आप हमें पैसे दो, हम तुम्हें पास करा देंगे। इन कोचिंग क्लासेज में कितना पैसा देना पडता है? एक-एक कोचिंग क्लास में 25 से लेकर 75 बच्चे तक होते हैं और डेढ़ लाख रुपए से लेकर तीन लाख रुपए तक बच्चे का वार्षिक खर्च होता है। जब मां-बाप देखते हैं कि उसके बच्चे की पढाई करने के लिए, उका भविष्य बनाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, तो वे कर्ज लेकर coaching classes करवाते हैं। स्कूल में टीचर आते नहीं हैं, पढ़ाई होती नहीं है और बच्चे पर इतना ज्यादा दबाव होता है कि वह खाना इत्यादि छोड़कर किताबें पढ़ने में लगा रहता है। उसे पास होना है और अगर किसी कारण से फेल हो गया, तो मां-बाप को शर्म आएगी और उसको भी आएगी और बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से बच्चे coaching classes में जाते हैं। ये coaching classes नहीं बल्कि शिक्षा के बूचड़खाने बन गए हैं। इसमें बच्चों का बचपन खत्म हो जाता है और कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं आपको दिल्ली का हाल बताता हूं कि साकेत से, वंसत बिहार से सफदरजंग एन्कलेव आदि की coaching classes से ग्यारह बजे तक बच्चा वापस लौटता है। वह आखिरी physics, chemistry की coaching classes से पढ़कर लौटता है। और फिर उसे सुबह छ: बजे उठना पड़ता है, ताकि वह साढ़े सात बजे स्कूल जा सके। यह विधेयक इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे हिन्दुस्तान के भविष्य का जो एक अन्त किया जा रहा है, उसको बचाया जा सकेगा, जो कहीं देखने की स्थिति में नहीं रह गया है।

सर, मैं एक ही बात कह रहा हूं। मै स्वयं दो बच्चों का पिता हूं और मेरे बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते हैं। यह विधेयक देख कर मैंने खुद आग्रह किया, क्योंकि यह जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, इसमें बच्चों को खत्म किया जा रहा है। हम रोते हैं, जब घर में अपने बच्चों का हाल देखते हैं। इसके लिए कुछ उपाय तो किया जाना चाहिए। कहां से हम इतना पैसा लाएं? डेढ लाख, दो लाख रुपये एक बच्चे की कोचिंग का एक साल का खर्च है। स्कूल का खर्च अलग है। उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का खर्च अलग है। यह फर्क हिन्दुस्तान में एक दास और स्वामी का भाव पैदा कर रहा है।

मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल से साढ़े सात किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, जिसका नाम है चामासारी। उस चामासारी गांव में विद्यालय नही है। दो महीने पहले मैं वहां गया था। वहां के लड़के और लड़कियां आठ किलोमीटीर पैदल चल कर मसूरी में घनानन्द स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। भगत दा यहां पर स्वयं बैठे हैं। वे बच्चे वहां तक पैदल .आते हैं और पैदल जाते हैं, क्योंकि पहाडी रास्ता होने के कारण वे वहां साइकिल भी नहीं चला सकते। अपनी आंखों के सामने वे देखते हैं कि करोड़पतियों के बच्चे, लाखों रुपये सालाना की फीस देने वाले बच्चे, उसी क्लास रूम में पढ़ने बच्चे उनके सामने चल कर उनको हिकारत की निगाह से देख कर जाते हैं कि तुम काले हिन्दुस्तान और हम अंग्रेजियत के जूतों में ढले अमीर मां-बाप के बच्चे हिन्दुस्तानी।

यह जो कोचिंग क्लासिज का धन्धा या बिजनेस है, यह हिन्दुस्तान में मालिक और दास, दो वर्ग पैदा कर रहा है। यह वह इंडिया पैदा कर रहा है, जो भारतवर्ष के विरुद्ध है। यह वह अर्जुन पैदा कर रहा है, जो एकलव्य के अंगूठे कटवाता है। यह वह द्रोणाचार्य पैदा कर रहा है, जो राजसी सत्ता की दासता के अंधे मोह में फंस कर एक योग्य और मेधावी छात्र को उसके भविष्य से वंचित कर देता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति मैडिकल कॉलेज, आई.आई.टी. और आई.आई.एम. में प्रवेश के लिए एक-एक करोड रुपया खर्च करता है, वह कहां से पैसा उठाएगा या कहां से पैदा करेगा? कहीं न कहीं से तो वह उस पैसे को वसूल करेगा ही करेगा

अन्त में मैं एक उल्लेख करना चाहूंगा। आज स्थिति कितनी भयावह बन गई है, इस पर हाल ही में एक फिल्म बनी - आरक्षण। यह कथा प्रभाकर और मिथिलेश के मध्य संघर्ष की कथा है। वह प्रभाकर, जो ईमानदारी से बच्चों को विद्यालय में पढ़ाना चाहता है, उस मिथिलेश के सामने हारा हुआ महसूस करता है, जो के.के. इंस्टीट्यूट चलाता है और अन्त में कहता है कि मैं तुमको जवाब दूंगा। जवाब देने के लिए उसके पास भ्रष्ट राजनेताओं का समर्थन जो होता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप हर प्रान्त में जा कर देख लीजिए, लगभग हर राजनेता ने हर मंत्री ने अपने यहां एक मैडिकल कॉलेज, एक बीएड़ कॉलेज, एक डेंटल कॉलेज, एक फलाना कॉलेज, एक ढिमाका कॉलेज खोला हुआ है। जो हेल्थ मिनिस्टर होता है, वह अपने प्रान्त में मैडिकल कॉलेज खोलता है, जो एजुकेशन मिनिस्टर होता है, वह अपने प्रान्त में बी.एड. का या फलाना-ढिमाका कॉलेज खोल कर करोडों रुपये के डोनेशन से उसमें प्रवेश करवाता है। हिन्दुस्तान के गरीब बच्चों को बचाएगा कौन? जिस व्यक्ति पर जिम्मेदारी होती है कि वह शोषक सामन्तों से सामान्य गरीब बच्चो को बचा कर उनको सामान्य फीस के आधार पर अच्छा भविष्य निर्मित करने का अवसर देगा, सुरक्षा देगा। लेकिन जब वह खुद ही इस पाप के धन्धे में शामिल होता है, वह खुद ही अपने नाम पर मैडिकल कॉलेज खोलता है और हेल्थ मिनिस्टर बनता है, तो उन गरीब बच्चों को कौन बचाएगा? कौन हिन्दुस्तान के एकलव्य को बचाएगा? इस परिस्थिति में यह जो मुनाफे के लिए शिक्षा का व्यापार चला है, यह भारत के विरुद्ध है, यह भारतीयता के विरुद्ध है, यह भारत की सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध एक पाप है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी मैं चुशूल गया था, जहां 1962 की लड़ाई हुई थी और जहां मेजर शैतान सिंह का बलिदान हुआ था। चुशूल गांव ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी। उस गांव में 60 साल के बाद पहला पोस्ट ग्रैजुएट अभी एक साल पहले बना है। यह तो उन सरहद के गांवों की कहानी है, जहां सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि वे सबसे अधिक देशभक्ति के साथ शत्रु के सामने खड़े होते हैं। बाकी लोगों के सामने एक उदाहरण होना चाहिए था कि देखो, सरहद के लोगों को हमने कितनी ढांचागत सुविधाएं प्रदान की हैं। हमने नहीं दीं। सरकार की यह जो शिक्षा नीति है, वह शिक्षा के विरुद्ध है, वह सामान्य भारतीय के विरुद्ध है, वह भारतीय तत्व के विरुद्ध है। जैसे गंगा का गंगत्व होता है, वैसे ही भारत की भारतीयता होती है इस भारतीयता के विरुद्ध ये कोचिंग क्लासेज हैं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करूंगा और चाहूंगा कि एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल न समझते हुए, इसको यह सदन एकमत से पारित करे, जैसे हम सचिन को एकमत से बधाई देते हैं, अग्नि मिसाइल पर एकमत से बधाई देते हैं, देश के किसी भी विशेष अवसर पर एकमत होकर, पार्टी के दायरे से ऊपर उठ कर हम एकजुट हो जाते हैं। यह विधेयक भी एक ऐसा विधेयक है, जिसे पूरा सदन एकजुट होकर हिन्दुस्तान के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, भारतवर्ष के भविष्य को बचाने के लिए पारित करे, तब हम भारतीयता की रक्षा कर सकेंगे।

4.00 P.M.

[श्री तरुण विजय]

मैं मोहन सिंह जी को बधाई देते हुए सदन से करबद्ध प्रार्थना और याचना करूंगा कि अपने बच्चों को इन कत्लखानों से बचाने के लिए कृपया इस विधेयक के आधार पर एक अच्छा कानून बनाए। यह सरकार कानून लाए और विपक्ष उसका साथ दे, तो हम एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।

श्री शादी लाल बत्रा (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय सदस्य, श्री मोहन सिंह जी यह एक ऐसा बिल लाए हैं, जिसने हरेक की भावना को जगाया और यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हिन्दुस्तान में शिक्षा कैसी हो।

महोदय, अगर हिन्दुस्तान को देखना है तो हिन्दुस्तान के गांवों को देखना होगा। एक शिक्षा शहर की है और एक शिक्षा गांव की है। जब हम उन दोनों शिक्षाओं का मुकाबला करें, तब आगे चलकर यह देख सकेंगे कि इस देश का विकास कैसे हो और देश की आने वाली पीढ़ी कैसे अनुशासित और पढ़ी-लिखी हो। मैंने किसी से पूछा था कि आपको कैसा बेटा चाहिए, गुणवान चाहिए या धनवान चाहिए? जवाब मिला कि मुझे बेटा धनवान चाहिए, मैं उसको धनवान बनाना चाहता हूं, क्योंकि गुणवान को तो वह खरीद लेगा। जब ऐसी भावना आ जाए, तब फिर वह शिक्षा कैसी होगी? तब शिक्षा एक व्यापारिक केन्द्र बन जाएगा, एक व्यापारिक सेंटर बन जाएगा और वह बन रहा है। आज बच्चा जब तीन साल का होता है, तब उसकी शिक्षा के लिए उसे नर्सरी क्लास में भेजने के समय हर बाप की यह इच्छा होती है कि स्कूल अच्छा हो, उसका नाम ठीक हो, उसके टीचर्स अच्छे हों। ऐसे स्कूल में नर्सरी में एडमिशन के लिए उसको, चार पांच या छः लाख की कैपिटेशन मनी देनी पड़ती है। अगर इतनी फीस वह नर्सरी में ही देता है और हर महीने दस हजार से पंद्रह हजार रुपए खर्च करता है, तो थोड़ा अंदाजा लगाइए कि मैट्रिक तक, मैट्रिक के बाद ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और उसके बाद यदि वह बच्चा टेक्निकल कोर्सेज में जाए तो और कितने करोड़ रुपए वह खर्च करेगा। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जब वह बच्चा बड़ा होगा, तब उसके मन में यही भावना पैदा होगी कि मेरे पालन-पोषण और शिक्षा पर जितने पैसे खर्च हुए, वह पैसा मैं कैसे वापस लूं। हमें यह देखना होगा कि हमने शिक्षा के लिए क्या किया और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षा के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको परमिशन देकर भी हम अपने आपका बहुत नुकसान करते हैं। अगर यह शिक्षा गवर्नमेंट के केन्द्र से हो या किसी सोसायटी से हो, जो एन.जी.ओज. हों, जिनके मन में देशभक्ति की भावना हो, जिनके मन में यह सोच हो कि हमें आने वाली पीढ़ी को सुधारना है, तब बात कुछ समझ में आती है, लेकिन जब किसी इंडिविजुअल को सारे कोर्सेज दे दिए जाएं, इंजिनियरिंग दे दी जाए, मेडिकल कॉलेजिज दे दिए जाएं और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए even B.Ed. तक दे दी जाए, तो उसका एक ही ध्येय होता है कि कितना पैसा कमाया जाए और वह कैसे कमाया जाए।

उपसभाध्यक्ष जी, जो NCTE (National Council for Teacher Education) है और नॉर्थ जोन में जिसका ऑफिस जयपुर में है, उसकी एक जीवित मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने B.Ed. कॉलेज खोलने के लिए परमिशन दी, एफिलिएशन दी, लेकिन जब कॉलेज खुला, तो उस कॉलेज की कहीं बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ उसके नाम का एक बोर्ड लगा हुआ था। उसमें टीचर्स नहीं थे, पढ़ाने की कोई शक्ति नहीं थी और उस कॉलेज में बच्चे जाते

नहीं थे। अंत में, बच्चों को एक आश्वासन दिया जाता था कि आप आओ, एग्जाम में बैठ जाना, रौल नम्बर लिख देना, आपको पास कर दिया जाएगा। आप कॉलेज में नहीं आओगे, आप क्लास में नहीं आओगे, आपका टाइम नहीं लगेगा, आप फेल भी नहीं होंगे और आप पास हो जाओगे, तो इन सारी चीजों की वे कितनी फीस लेते थे, इसके लिए कितने पैसे लेते थे, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं।

ऐसे जितने भी केन्द्र खुले हैं, उन केन्द्रों पर कोई अनुशासन नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, ताकि उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। इसके लिए एक inspection कमेटी बनाई जाती है। इस तरह से दो-तीन बार कमेटियां बनीं और उन कमेटियों की भी अपनी फीस हो गई। वे कहने लगे कि अगर आपको अपने कॉलेज को पास करवाना है, अगर आपको अपने शिक्षा के केन्द्र को आगे ले जाना है, तो हमें इतनी फीस देनी होगी। फीस मिलने के बाद वे बिना inspection किए उनके हक में अपनी रिपोर्ट दे देती हैं। अगर वे उनकी merits and demerits को देख कर अपनी रिपोर्ट देतीं, तो इससे स्थिति सुधरती, लेकिन उन्होंने इसको धन कमाने का एक रास्ता बना लिया कि inspection commititee में जाओ और धन कमा कर आओ।

महोदय, जब तक इसके लिए accountability फिक्स नहीं करेंगे कि आपने जो रिपोर्ट दी थी वह गलत दी थी, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हर शिक्षक की accountability फिक्स होनी चाहिए। यह accountability private institutions की भी हो कि आपने बच्चों के लिए क्या किया। आपने उनको कितनी सुविधाएं दीं और उन सुविधाओं के लिए आपने उनसे कितनी फीस ली? आज नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के जो भी शिक्षण संस्थान खुले हैं, वे एक industry की तरह हैं। पहले विद्यार्थियों में गुरु के प्रति एक भावना होती थी और वे उम्र भर गुरु के प्रति नतमस्तक होकर आगे बढ़ते थे, लेकिन आज उस भावना का अंत हो रहा है। अब तो वे कहते हैं कि यह मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, क्योंकि आज अपने शिक्षकों के साथ सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, आदि हर काम करने में बड़ी आसानी होती है और शिक्षक भी यह सोचता है कि मैं इन्हें अपना दोस्त बना कर चलता हूं। अगर ऐसी शिक्षा पद्धति भारत में आए, तो भारत का क्या होगा? भारतवर्ष, जिसके लिए हम कह सकते थे और जिसके लिए हम एक आशा रखते थे कि हमारा भारतवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का एक प्रमुख देश था, वह आज खत्म हो रही है। आपस में आज मान-सम्मान, बडों को मान-सम्मान और शिक्षकों का मान-सम्मान, ये सब खत्म हो रहे हैं। इसके पीछे तो एक ही बात है कि उस शिक्षा का उदारीकरण न करके, हमने उसका व्यापारीकरण कर दिया और उससे पैसा कमाने लगे।

महोदय, अगर हम गांवों की ओर देखें, तो पाएंगे कि गांवों में शिक्षा के साधन नहीं हैं। गांव का बच्चा, चाहे वह किसान का हो या मजदूर का हो, कहां जाएगा? वह पैसे दे नहीं सकता है और उसकी मेहनत का जो फल है, वह उसको मिल नहीं सकता है, तो ऐसे में क्या होगा? यह देखना होगा कि उस बच्चे ने किस कुल में जन्म लिया है। उसका बाप कितना धनवान है और उसके बाप के पर्स में कितना पैसा है। अगर उसके बाप के पर्स में पैसे हैं, तो उसके बच्चे को कोई भी डिग्री मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ बी.ए. करेगा, बल्कि वह डॉक्टरी की भी डिग्री लेगा, इंजीनियरिंग की भी डिग्री लेगा और सब डिग्री लेने के बाद वह अपने व्यवसाय में आगे बढ़ेगा। अगर ऐसा होगा, तो इसके लिए हमारा समाज कितना जिम्मेदार होगा? समाज का हर व्यक्ति इसके लिए अपना क्या योगदान दे रहा है? जब

[श्री शादी लाल बत्रा]

समाज का व्यक्ति योगदान नहीं देता है, तो कोई बात नहीं बनती है। मैं जहां इस बिल का समर्थन कर रहा हूं, वहीं मैं यह भी चाहूंगा कि शिक्षा के काम को किसी individual को न देकर, किसी व्यक्ति विशेष को न देकर, सरकारी संस्था या किसी NGO को दिया जाए, ताकि उन पर सरकार का कोई कंट्रोल हो और उन पर अंकुश लग सके।

अगर ऐसा नहीं होगा, तो हर individual यह चाहेगा कि मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है और फिर वह कुछ टीचर्स के साथ जो बिल्कुल अनपढ़ बच्चे हैं, उनको लेकर एक स्कूल खोल देगा। स्कूल खोलने के बाद उस पर धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी और तब वह कहेगा कि मैंने बहुत अच्छा कार्य कर लिया, मैंने तो एक factory खोल ली। जिस भारतवर्ष की हम कल्पना किया करते थे कि एक गुरू के प्रति कितना आदर करें और गुरू हमें कैसी शिक्षा दें, ये सारी सोच खत्म हो रही है। आज हम दूसरे देशों का अनुकरण करने जा रहे हैं। अगर इसको दूसरे ढंग से देखें, तो वह इस प्रकार है कि जो बच्चा अच्छा पढ़-लिख सकता है, वह एम.डी. कर लेता है और एम.डी. करने के बाद वह यह सोचता है कि यह देश मेरे लिए नहीं है। आज हमारे गुणवान बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, तो उसके पीछे भावना क्या है? उसके पीछे एक ही भावना है, एक ही सोच है। वे कहते हैं कि अपने देश में हमने इतनी मेहनत की, हमने इतनी डिग्रियां लीं ओर डिग्रियां लेने के बाद आज हमें जो मान-सम्मान मिलना चाहिए था, वह मान-सम्मान नहीं मिल रहा। जब हम दूसरे देशों में जाएंगे, तो वहां केवल pay and allowances ही नहीं मिलेंगे, बल्कि वहां हमें इतना सुख मिलेगा कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम इस चीज को रोकना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश का युवा अपने देश में रहे और वह दूसरे देशों में जाने की बात न कर अपने देश की सेवा करे, तो हमें यही सोचना होगा कि हम उसको अनुशासित और हर तरीके के सुख-साधन से सम्पन्न एक वातावरण दें, जिसे देने में हम आज विफल हो रहे हैं, हम उन्हें वह वातावरण नहीं दे पा रहे हैं। जो वैसा वातावरण नहीं दे पाये, ऐसा अगर शिक्षक हो, तो हमारा भविष्य कैसा होगा? आइए हम सोचें कि अगर भविष्य के लिए कुछ करना है, अगर हमें अपने देश को ऊपर उठाना है, आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा नागरिक बनाना है, जो अनुशासित हो, शिक्षित हो और जिसमें देश के प्रति प्रेम भी जागे, तो फिर हमें कुछ सोचना होगा। हम अपने बच्चों को क्या पारिश्रमिक देने जा रहे हैं, आज इस बात की चिन्ता है। मोहन सिंह जी ने इस बात को उठाया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, इसके पीछे बहुत कुछ है कि हम आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचेंगे। हम आने वाली पीढी को शिक्षित करके उनको यह मर्यादा देंगे। जब हम उनको यह मर्यादा देंगे, तो हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए हमें अपने-आप में एक संकल्प लेना होगा। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हमें शिक्षा को व्यापार नहीं बनाना है। हमें यह संकल्प लेना होगा कि शिक्षा तो एक दान है, हमें सेवा करके अच्छे नागरिक बनाने हैं और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना है।

उपसभाध्यक्ष जी, आज यह बिल आया है। चूंकि यह एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल है, तो इस बिल को कैसे पास करेंगे? अगर यह बिल पास हो भी जाएगा, तो इसमें आगे जाकर और भी technicalities आएंगी, तो मैं उन technicalities में न जाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य और सोच के साथ यह बिल लाया गया है, वह वाकई

सराहनीय है। उसकी तो हम सराहना करते ही हैं, लेकिन इस पर भारत सरकार को भी कुछ न कुछ करके, शिक्षा के प्रति concern होकर इसे हर प्रकार से improve करने के लिए जो कार्य करना है, उसे करना चाहिए। यह बिल पास हो, इसके पास होने के बाद इस पर हमारे एजूकेशन मिनिस्टर और हमारी गवर्नमैंट यह विचार करे कि हमारे भारतवर्ष में शिक्षा का स्टैंडर्ड जो कम हो रहा है, उसको हम कम न होने दें, बल्कि हम अपने हर नागरिक को ऐसी सुविधाएं दें, जिससे उसको शिक्षा भी प्राप्त हो और उसमें देश के प्रति मान-सम्मान और आदर की भावना भी पैदा हो। यह तब हो सकता है, जब वह अपने गुरू और मां-बाप का आदर करे। फिर हम उसे मॉडर्न शिक्षा न दें, बल्कि उसका सहारा लेकर अपनी भारतीय शिक्षा को ऊपर रखें और वे भारतीय शिक्षा ग्रहण करें। इन्हीं शब्दों के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI V.P. SINGH BADNORE (Rajasthan): Sir, I stand to speak on the Pre-examination Coaching Centres Regulatory Authority Bill, 2010, moved by Shri Mohan Singh *ji*, a stalwart in the House. Before I get to the Bill, firstly I want to say that there is a lot of merit in this Bill. Secondly, I think, let us not confuse what the sense of this Bill is and what the Member really has put fourth. If you start saying that the coaching classes are wrong, that is not the sense of this Bill. We are not talking about the tuitions or the coaching classes. We are talking of the coaching centres which have mushroomed all over the country. Some places have become hubs, like Kota. Jaipur is also becoming a hub. What are these centres doing? They are coaching students who have done 10+2 for pre-medical, for engineering. So, they have to have the expertise. Otherwise, people will not go to them.

They have to have the best of the professors. They have to have visiting professors. They have to have retired people who have done well. Then only they can coach. These centres, which have come up, have to show what the placements have been. If something goes wrong, the boy really suffers. Basically this is to control this. There are a lot of centres which say that they are so good. They advertise in big ways, but actually they are hollow. These are the things that have to be regulated. Coaching classes or specialisation is required in every field. Even for civil services examination — IAS or IPS — there are coaching centres. They have to be taught. Otherwise, they will not be able to get into it.

Take games. If you want to get into Olympics, you have to have coaching and you have to have specialisation. You have to work hard to get into it. But they need to be regulated. This is the sense of the Bill. This is what Mohan Singhji wants. Why does he want it? He wants it because they are unrecognised in the field. They are hollow. They are fraud institutions. It has to be looked into. Two, there should be a prescribed fee. You just cannot charge anything and get away with it. That has to be looked into. They should have required classes, toilets, etc. All these things have to be there. This is a regulatory Bill for those centres. I think this is a very good idea. These centres are required. They are professional

[Shri V.P. Singh Badnore]

institutions. But along with that, they need some regulation. That is why this Bill is mooted. I feel that it is in the right spirit. It has merit and I feel that this must be regulated.

Education is given in the Concurrent List. It means both the Centre and the States can make laws. If the Centre makes a law, it has to go to the States. They can change it a little bit, but the thing is that it should come from the Centre. There are other centres also. They should also come into that. There are tennis classes, swimming classes, etc. There are cricket coaching academies which have come up in the name of big players. They are all there, and they are doing a good job. I am not saying that they are not. But we have to see how much fee is being charged. Are they doing the right work? All these things have to be regulated. This is a regulatory Bill for the centres. I agree with it, and I totally support it. Thank you very much.

श्री नरेन्द्र बुढानिया (राजस्थान): सर, यह एक बहुत ही महत्तवपूर्ण विषय है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सर, जिस देश में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, वह देश हमेशा तरक्की करता है। आज हर गरीब, मजदूर, कर्मचारी या शिक्षाविद अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है।

आजादी से पहले हमारे देश के अंदर शिक्षा काफी कम थी। स्कूल तो होते ही नहीं थे। मैं एक गांव से आता हूं और पुराने लोगों से सुनता हूं कि एक बच्चे को पढ़ने के लिए 50-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। प्राइमरी स्कूल्स बहुत कम थे और Secondary व Higher Secondary Schools तो बड़े-बड़े शहरों में होते थे, लेकिन आजादी के बाद हमारे देश में शिक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी योजना तैयार हुई और जगह-जगह स्कूल्स खोलने को निर्णय लिया गया।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मै कह सकता हूं कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर मिडिल स्कूल न हो या प्राइमरी स्कूल न हो। आज हर दो-तीन गांव के पीछे Secondary school है निश्चित रूप से हमारे देश ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। हमारी यू.पी.ए. की सरकार ने भी शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। मैं हमारी यू.पी.ए. की चेयर-पर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होने सर्व-शिक्षा अभियान का निर्णय लिया, मिड डे मील प्रोग्राम का निर्णय लिया, हमारे गांव के अंदर भी कोई बच्चा बिना पढ़े न रहे, उसके लिए सब प्रकार की सुविधा का ख्याल रखा, बच्चों के लिए स्कूल में भोजन की व्यवस्था रखी और इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से देश में शिक्षा बढ़ी उस में बड़े-बड़े घरानों ने शिक्षा केन्द्रों पर कब्जा करने की कोशिश की और आज पैसे वाले लोगों के चंगुल में हमारी शिक्षा आती जा रही है। आज जिस प्रकार से देश में प्राइवेट मेडिकन कॉलेजेज, इंजीनियांरिग कॉलेजेज, बी.एड कॉलेजेज खुल रहे हैं, यह चिंता का विषय है। महोदय, अगर हम इस देश

में अच्छे शिक्षक पैदा नहीं करेंगे, अच्छे डॉक्टर्स पैदा नहीं करेंगे, अच्छे इंजीनियर्स पैदा नहीं करेंगे, अच्छे वैज्ञानिक पैदा नहीं करेंगे, तो हमारा देश बहुत नुकसान उठा सकता है। आज इस बारे में देश में बहुत चिंता बनी हुई है। महोदय, जिस प्रकार से शिक्षा का व्यावसायीकरण हो रहा है, यह एक चिंता का विषय है। आज हर मां-बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, उन्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहता है। मैं श्री शादी लाल बत्रा जी की बात से सहमत हूं कि आज गांव की शिक्षा अलग है और शहरों की शिक्षा अलग है, गरीब और अमीर बच्चे की शिक्षा अलग है। इस भेदभाव को खत्म करना आवश्यक है। इस दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, श्री मोहन सिंह जी ने आज जो बिल पेश किया है, यह बहुत ही अच्छा है। आज चिंता इस बात की है कि ये जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, मै इन कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ नहीं हूं, कोचिंग सेंटर्स होने चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन इन कोचिंग सेंटर्स की जिस प्रकार से बाढ़ आ गयी है, जगह-जगह शिक्षा का व्यावसायीकरण हो रहा है, बच्चों से मनमानी फीस वसूल की जाती है, यह गंभीर चिंता का विषय है। आज चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, चाहे आई.ए.एस. हो, चाहे स्टेट सर्विसेज हों, हर शिक्षा के लिए कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। और इन कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग के नाम पर करोडों रुपए लिए जा रहे हैं। इनमें न केवल पैसे वसूल किए जाते हैं बल्कि इन सेंटर्स पर बच्चों को किस प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है, इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। यदि आज हमने इस क्षेत्र को ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं समझता हूं कि आनेवाले समय में हालात बहुत बिगड सकती है।

महोदय, आज प्राइवेट विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। उनमें क्या हो रहा है? वहां कोई देखने वाला नहीं है कि वहां किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, किस प्रकार से बच्चों को पढाया जा रहा है, किस प्रकार से वहां छात्रों को डिग्रियां दी जा रही हैं, उसे देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज इन सब चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। इन्ही बातों पर ध्यान देने के लिए मोहन सिंह जी का यह बिल आया है जोकि बहुत अच्छा बिल है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए एक बोर्ड होना चाहिए जोकि इन कोचिंग सेंटर्स को नियंत्रित करे। वह देखे कि कोचिंग सेंटर चलाने वाला कौन व्यक्ति है? वह कोई व्यवसायी तो नहीं है, उसका उद्देश्य पैसा कमाना तो नहीं है, कोचिंग सेंटर चलाने वाले की क्वालिफिकेशन क्या है इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

उसकी बेकग्राउंड क्या है, कौन-कौन से विषय की वह कोचिंग देगा? जो कोचिंग देने वाले हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और बेकग्राउंड क्या है? इन सब चीजों को देखना नितांत आवश्यक है और इसके लिए एक बोर्ड होना चाहिए। मैंने खुद देखा है, जैसा कि अभी कोटा का नाम आया, उपसभाध्यक्ष जी, अगर मैं उदाहरण दूं, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, कि गांव के रहने वाले लोग अपना सब कुछ बेच कर अपने बच्चों को कोचिंग के लिए वहां कोटा में भेजते हैं, जहां तीन-तीन, चार-चार साल बच्चों को कोचिंग कराते हैं, फिर भी उनको उचित परिणाम नहीं मिलता है। इन कारण से लोगों की ऐसी हालत हुई है कि आप समझ नहीं सकते।

[श्री नरेन्द्र बुढानिया]

यह जो इस प्रकार का बिल आया है कि इन पर नियंत्रण होना चाहिए और इस नियंत्रण का प्रावधान ही इस बिल में रखा है, इसके लिए मैं मोहन सिंह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इनके बिल का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाएगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. नजमा ए. हेपतुल्ला (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद, जो आपने मुझे एलाउ किया। पार्लियामेंट में आने से पहले मैं कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के जो तजुर्बे हैं वे मैं अपने हाउस के सामने रखूं। हम लोगों को जब आजादी मिली, तब हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री ने अपने सबसे काबिल साथी मौलाना अबुल कलाम आजाद को एजुकेशन का मिनिस्टर बनाया। मुझे याद है कि यही अप्रैल की शायद 27 तारीख का उनका एक लैटर है, जो हमारी पार्लियामेंट की लायब्रेरी में है, 1948 में उन्होंने यह लैटर कंस्टीट्यूट असेम्बली को लिखा था कि एजुकेशन को डिफेन्स के बराबर दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जब मुल्क को जरूरत होती है, आपत्ति आती है, आक्रमण होता है, तो उसकी डिफेन्स के लिए सरकार कहीं न कहीं से धनराशि जमा करती है, आज जिन हालात से हम दूसरों की गुलामी से बाहर निकले हैं, हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम एजुकेशन को डिफेन्स के बराबर समझें और उसका एलोकेशन सबसे ज्यादा रखें। अफसोस की बात है कि वर्षों गुजर गए, एजुकेशन को उसका वह दर्जा नहीं मिला, जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने सोचा था। एक बात उन्होंने और कही थी कि मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा, अगर मेरे देश के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर दूसरे मुल्कों में जाएं, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे देश के इंस्टीटयूशन्स ऐसे बनें, तक्षशिला और नालंदा की तरह, जहां सदियों पहले बच्चे बाहर से तालीम, इल्म, शिक्षा हासिल करने के लिए हमारे देश में आते थे। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि किसी भी मुल्क की तरक्की इस बात से नहीं नापी जाती कि उस मुल्क में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने कारखाने हैं, बल्कि क्वालिटी ऑफ माइंड जो उसके पीछे होगा, उससे माना जाता है कि वह मुल्क कितना तरक्कीयाफ्ता है। He wanted to build a quality of mind and that quality of mind can only come from very good institution which he expected to come.

सर, मैंने भी स्कूल में पढा है। हमें कभी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस जमाने में इतने बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते थे। जब मैं मैट्रिक में पढती थी, सांइस का सब्जेक्ट था, हमारी क्लास में 15 बच्चे थे, टीचर पर्सनली हम लोगों की तरफ ध्यान देती थी। आज किसी भी स्कूल में किसी क्लास में 30-40 बच्चों से कम नहीं होते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट एडेड स्कूल हो। इसी तरह जब कॉलेज में मैं एम.एस.सी. में पढ़ रही थी, हमें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी और वह इसलिए कि हम लोग एम.एस.सी. प्रिवीयस में सात लोग थे, तो जितने हमारे टीचर्स होते थे वे पर्सनली हम लोगों को देखते थे, मगर आज हम यह कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई टीचर हर बच्चे पर ध्यान दें और अगर कोई बच्चा पढ़ने में पीछे है या उसको कोचिंग की जरूरत है तो उसके लिए स्कूल में ही उसकी सुविधा हो। तो यह मजबूरी हो जाती है कि कोचिंग क्लास में लोग अपने बच्चों को भेजें।

आप मिसाल ले लीजिए कि मेरे घर में मेरा कुक है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। न बाप पढा-लिखा है, न मां पढी-लिखी है। उस बच्चे को अगर कोचिंग जी जरूरत

पड़ती है, तो वह किधर जाएगा? हम तो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, क्योंकि हम पढ़े-लिखे थे, हमें इतना तर्जुबा था कि हम घर पर ही अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करते थे। हर बच्चे को कुछ न कुछ कोचिंग की जरूरत पड़ती है। अगर मां-बाप कोचिंग नहीं दे सकते हैं, तो बच्चों को कोचिंग क्लास में जाना ही पड़ेगा। खास तौर पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों को कोचिंग की जरूरत पड़ती है। अमरीका और यूरोप में अगर कोई बच्चा अपनी क्लास में average से नीचे होता है, तो स्कूल के अंदर ही उसके लिए Specialized coaching की facility होती है। आज हमारे देश में यह सुविधा नहीं है। Right to Eductions का बिल हमारे यहां पास हुआ। यह बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने 60 वर्षों के बाद Right to Education के बारे में सोचा, लेकिन केवल Right to Education का बिल पास हो जाने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। हमारे पास इतने resources होने चाहिए कि हम इतने स्कूल बना सकें कि देश मे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, वे उनमें दाखिल हो सकें। आपको भी तजुर्बा होगा, मुझे भी यह तजुर्बा है और हमारे यहां बैठे हुए हाउस के बाकी मेंबर्स को भी यह तजुर्बा होगा कि जब admission का समय आता है, तो हमारे घरों में कोई न कोई application लेकर आता है कि आप अपने कोटे में से मेरे बच्चे को सेंट्रल स्कूल में या अगर कहीं आपकी पहचान है, तो किसी दूसरे स्कूल में दाखिला दिला दीजिए। जिस दिन हमारे मुल्क में Right to Education को compulsory education का दर्जा मिल जाएगा, जिस दिन हम इतने institutions बना देंगे कि वे बच्चे स्कूलों में अच्छी तालीम हासिल कर सकें, उस दिन तक हमें Coaching classes की जरूरत पड़ेगी।

जिस धारणा को लेकर, जिस सोच को लेकर मोहन सिंह जी यह बिल यहां पर लाए है, मै उसे महसूस करती हूं और सपोर्ट करती हूं। कोचिंग तो होगी, क्योंकि कोचिंग की जरूरत सबको पड़ती है, लेकिन जिस तरीके से coaching classes में exploitation होता है या वे गलत बात बोलते हैं या उनकी फीस में अंतर है कोई ज्यादा पैसे लेता है, कोई कम पैसे लेता है, इसको regulate करने की जरूरत है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि बाकी सदस्यों ने भी इस बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं केवल इतना कहूंगी कि उन्होने बिल में जो प्रस्ताव रखा है, जो उनका मकसद है, मैं समझती हूं कि इसके लिए कोई regulation होना चाहिए, कोई controlling authority होनी चाहिए, क्योंकि education कोई Central subject नहीं है, यह Concurrent Subject है। मैं समझती हूं कि अगर इस तरह का कोई direction state level पर भी भेजा जाए कि वे अपनी स्टेट्स में इन coaching classes पर कंट्रोल रखें, तो अच्छा होगा और मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Najmaji. Now Minister is to reply.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): Thank you, Sir. At the outset, I would like to thank all my colleagues who have participated in the debate today. I would also like to thank our senior colleague, Mohan Singhji, for the sensitivity with which he actually brought this Private Member’s Bill. We have closely listened to the Members who have participated in the deliberations. Many issues have been raised about the quality of our schools, the quality of our teachers and accessibility.

[Shrimati D. Purandeswari]

But largely and most importantly the issue is whether we require coaching classes for our children or not. If we follow the debate very intently and closely, one aspect that comes up very clearly and definitely in the entire discussion is, largely in between the lines, whether we really need coaching classes today. But, I think, the emphasis was more on how we can improve our examination and teaching processes. I think, that is largely what the discussion was all about today. Many issues have been raised. I will, in the course of my reply, try to allay every apprehension that has been raised by my respected colleagues.

Sir, let me start with what Najma Heptullaji has just now said. She made a reference to the first Education Minister, Shri Maulana Abul Kalam Azad. I would like to apprise the House that recognising the contributions made by Shri Maulana Abul Kalam Azad, we have actually declared 15th of November, which is the birthday of Maulanaji, as “Education Day”. On last year's National Education Day, we had launched शिक्षा का हक अभियान।

It only emphasizes that our Government has been giving great importance to education. She has also gone on to emphasize that definitely country's progress must be reflected in the brainpower of that country. Sir, all of us agree with that we recognize the 21st Century as a ‘Knowledge Century’, I am sure everybody will agree with me that knowledge or brainpower must be reflected in the country's advancement, its competitiveness and also in its human capital. Human capital is the investment that we make in the human resources of that country. Therefore, I don't think there can be a better investment than education that we can make in our human resources. Having said that, I must also add that education has been receiving great importance and priority by the UPA Government. If we look at the comparative allocations that we have made in the Tenth Plan Period and the Eleventh Plan Period, in the Tenth Plan Period, if our allocation for education was about 9 per cent of the Gross Budgetary Support, in the Eleventh Plan Period it was 19 per cent of the Gross Budgetary Support, which the Members do know. Therefore, the Eleventh Plan Period has also been rightfully called the Education Plan, I am only emphasizing this to reflect the importance that our Government has been giving to education as we know for a fact that it is education that is critical to the development and progress of any country. Coming to Shri Mohan Singhji, he has raised many issues, more particularly, he has raised the issue of curriculum being neglected in schools where coaching centres are actually given more importance and, therefore, the school curriculum or education in schools has been grossly neglected. Sir, let me take this opportunity to apprise or to keep my hon. colleagues informed that it is keeping this in view that we realized that we need to

bring in an education system that will focus largely on the holistic development of the child. This has been a question or an apprehension or a concern raised not only by Shri Mohan Singh but by many of my colleagues who have actually participated in the deliberations today. We, from the Government of India, the MHRD, have looked into this aspect of focussing on the holistic development of the child and this is the reason why we had actually brought in the Continuous Comprehensive Evaluation in the place of actually having yearly exams for the child, which actually focussed more on only attaining marks and rote learning. Sir, the Continuous Comprehensive Evaluation, under which the child is evaluated, focusses on the complete development of the child; looks at the participation and progress of the child not only in scholastic but even in co-scholastic areas also. So this, we believe, will largely contribute to the complete development of the child and will also encourage the analytical skills of the child. But, however, Sir, as has rightly been pointed out by Shri V.P. Singh Badnore, we know for a fact that education is a Concurrent Subject and it is up to the State Governments and the State Boards even to take a step forward and support the efforts that we from the MHRD are doing. Under the Central Board of Secondary Education, we have around 12,000 schools as against the 12 lakh schools, which are the Government and Government aided schools alone, that exist in our country. So, I must emphasize that we have brought in the Continuous Comprehensive Evaluation in our own Central Schools, which are the Kendriya Vidyalayas and the Navodaya Vidyalayas. Our request to the State Boards has been to look into whether they could adopt the CCE to ensure that the holistic development of the child is actually given great importance. This was put forth in COBSE, which is, the highest Council for Boards of Secondary Education, to see if the State Boards were willing to adopt it. Sir, there was no resistance to the idea of CCE. The Boards rather felt that they would wait to see the success that the CBSE would achieve in implementing the CCE and then would look at whether they could actually adopt the CEE practice.

So, Sir, we firmly believe that,–the Members were also very much concerned about the coaching classes–when we bring in the CCE, there will be a weaning-away from coaching classes because, here, it is not the marks that will be given high priority and importance, but rather the overall development of the child, and the day-to-day performance of the child will, actually, be taken into consideration. So, this would, actually, help us in ensuring that the child would not have to undergo the grill of going to a coaching class and this would also help the parents because it would ease the pressure which they undergo.

Sir, Mohan Singhji and many others have also raised the issue of capitation fee. When children don't get through in entrance exams, then, there is the issue of capitation fee which comes up. I would also like to remind the House that we intend

[Shrimati D. Purandeswari]

to bring in the Unfair Practices in Educational Institutions Bill. This Bill, if supported by all my respected friends, can become legislation and only then can we, actually, take action against such institutions which are charging capitation fees. Sir, under the proposed legislation, the institutions would, actually, have to make it known, that is, they have to come with a break-up of why they are, actually, charging a particular sum of fee, and they will have to substantiate why the fee is being charged. And, if the child or the parent finds that the institution is not living up to the declarations made by it, then, definitely, under the legislation, action can be initiated against such institutions. I think the whole House and my colleagues will come forward and support the Bill, so that we will make sure that the capitation fee monster, which is looming large over our heads, is scuttled.

Sir, there were also issues raised about the pupil-teacher ratio in schools as well as in colleges. Under the Right to Education Act, which is a very historic Act that we have passed,—it was notified on the 1st April, 2010—we have ensured that the pupil-teacher ratio is fixed in the legislation itself, which means that for every 30 children, we need to have one teacher. And in the higher educational institutions, looking at the Central institutions itself, we have laid down a norm of 1:10 pupil-teacher ratio. So, this would ensure that qualitative education is being imparted to the child. But, of course, no one can undermine the importance of having qualitative teachers in our schools and in our classrooms. There is a very old saying which goes that an average teacher teaches, a good teacher explains, an excellent teacher illustrates, but a superior teacher illustrates and inspires. I think we need that fraternity of teachers in our schools who would help children not only in terms of education, but also in identifying the invate qualities in a child, the latent, dormant, potential in a child, and helping these talents come forward. Sir, a couple of Members here raised the issue of quality of B.Ed, schools in our country. The Central Government had superseded the General Council of the NCTE and has also constituted a six-member committee to examine the powers and functions of the Council. The NCTE has now taken several steps to reform the processes of granting recognitions to B.Ed, schools. So, this would, definitely, improve the quality of teachers in our schools. Besides this, we have also introduced the Teacher Eligibility Test (TET) at the State level and the TET for teachers coming into the Central schools itself. This is, in a way, to check national standards for qualitative teachers, to ensure that qualitative teachers come into the system, be it at the State level or at the Central school level. Sir, coming to absenteeism of teachers in schools—there was a reference made to absenteeism of teachers in schools—the Educational Consultants India Limited (Ed.CIL) had constituted a Technical Support Group for the Sarva Shiksha Abhiyan to look into this issue of teacher absenteeism in schools.

Their finding had said that the average attendance rate of teachers was around 81.7 per cent in the primary schools and 80.5 per cent in the upper primary schools. However, this is not to undermine the fact that we would want to have cent per cent attendance in our schools. However, measures should also be taken by the State Governments to closely supervise the schools. But let us also not forget, Sir, that under the RTE, we have school management committees which would be constituted in schools, which can, actually, closely monitor the absenteeism of schools and the SCPCRs which is the State Commission for Protection of Child Rights. And the National Commission for Protection of Child Rights also could look at the availability of teachers as an entitlement to ensure that the teachers are in school to impart qualitative education to the children. Sir, coming to the reform in the examination system, I had already made a mention of the CCE. But when we look at the multiplicity of exams that exist in our country, it is, in a way, contributing to the mushrooming of coaching centres or coaching schools as we are deliberating today. In the Ministry of Human Resource Development, there is a serious deliberation on whether we can bring about a common examination across the country for entrance into professional schools, and for that, we would actually need to have a core curriculum in core subjects like science and mathematics and commerce. NCERT had already looked into bringing in a core curriculum in science and mathematics, and commerce is on the way. It is due to be completed, and, if there is a common exam across the country, Sir, we largely believe that the multiplicity of exams can actually come down and this common exam can actually have an aptitudinal test, which would ensure that a child conning into professional institutions would have an aptitude to actually educate himself or herself in professional and technical education. This, Sir, we are looking at, introducing it initially in our Central institutions, and we have requested the States to look into the aspect of them adopting it, in case they want to, and, we leave the decision to the State Boards and State Governments whether they would want to adopt a common entrance exam or not. But for the Central Institution, we are looking at bringing in a common entrance exam by merging AIEE and JEE, which is still in the deliberation process, but if all stakeholders support us, then, probably, we would be bringing this in, and if we succeed, I am sure the State Governments would look into whether they could actually follow it up. Sir, of course, there was an issue of monitoring, which had actually come up. But, may I also take this opportunity to apprise the House that under the *Sarva Shiksha Abhiyan,* two per cent of the allocations made for the district can actually be used for monitoring the success of the schools of that particular district? So, they could use this in innovative ways to ensure that children do come to schools, they are present in schools, their attendance is not manipulated, and to also ensure that the teachers are available in schools. There was also a reference made about how do we actually give coaching to those children

[Shrimati D. Purandeswari]

belonging to disadvantaged sections of society, living in rural areas also, children studying In higher education institutions to strengthen themselves in education. Under the UGC, we have very many schemes which actually give coaching to children belonging to the disadvantaged sections. Sir, we have the remedial coaching for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and minorities. This is to improve the academic skills and also the linguistic proficiency of students, which is, today, a very, very large issue. We also have the Equal Opportunity Centres in colleges. Sir, This is to oversee the effective impiementation of policies and programmes for the disadvantaged groups, and to also provide guidance for them by counseling them. Sir, the UGC also supports coaching for NET and SLET

It is largely for SC/ST/OCB to prepare children in case they are so interested in coming into the teaching profession. They are given coaching and guidance so that they could clear NETnd SLET exams.

Sir, we also have schemes for persons with disabilities supported by the UGC. Under this, hand-holding is given to children who are physically challenged. Sir, the very provision of weightage for school performance under the joint exam of IIT and JEE, which has been recommended by Ramaswami Committee, again emphasizes the fact that we do give education in schools a greater importance than children going to coaching classes and getting, probably, support and ensure that they crack some IIT exam and get into IITs without an aptitude for actually getting into IIT.

So, I think, largely, when the Government is holistically looking at reforming the examination process, the teaching process which we strongly believe will wean away the children from coaching classes, when we have schemes and provision within the UGC and within our own Ministry which would actually give support to children belonging to disadvantaged sections of the society so that they can actually avail quality education and become productive citizens of a great nation like India, I would request the hon. Member and my most respected learned colleague by taking all these issues into consideration to kindly withdraw the Bill and support the Government in all its efforts. Thank you.

श्री मोहन सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस पक्ष और उस पक्ष के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे बिल की अंतर्निहित भावनाओं को ठीक से समझा है। माननीय मंत्री जी ने उसी भावना को समझते हुए कारगर उत्तर दिया है। माननीय मंत्री जी ने शिक्षा के बारे में कहा है कि भारत सरकार उसमें सुधार करने के लिए पहल करेगी। शिक्षा की गुणवत्ता अध्यापक की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करती है। शिक्षा की गुणवत्ता हमारे देश की प्रमुख समस्या है। आज इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, जिसके बारे में भारत सरकार गंभीरता पूर्वक सोचेगी। यदि पूरे देश में एंट्रेंस परीक्षाएं एक साथ हों, तो इसमें बहुत कुछ सुधार हो सकता है और राज्य स्तर पर जो नकल की प्रवृत्ति फैली हुई है,

उसको भी रोका जा सकता है। मैं इस विधेयक को पेश करके भारत सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता था। पूरी डिबेट सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सरकार ने और माननीय सदन ने मेरे विधेयक की मंशा को समझा है। मैं समझता हूं कि विधेयक को पास करने की बजाए, इसकी मंशा को समझ लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इसको वोट डाउन नहीं करना चाहता। यदि सदन और माननीय मंत्री जी की इच्छा हो तो मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं।

This bill was, by leave, withdrawn

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010
(INSERTION OF NEW ARTICLE 371J)

SHRI BHAGAT SINGH KOSHYARI (Uttarakhand): Sir, I beg to move:

That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संविधान संशोधन विधेयक, 2010 के लिए प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाए।

मान्यवर, उत्तराखंड राज्य हमारे देश का 27वां राज्य है। सन 2000 मे तत्कालीन एन.डी.ए. सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ के साथ उत्तराखंड राज्य का निर्माण संसद के सभी दलों के समर्थन के साथ किया। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू-कश्मीर तक अन्य जो पहाड़ी राज्य हैं, इनमें बहुत कुछ समानताएं हैं। हालांकि समस्याएं सबकी एक-सी हैं, लेकिन सरकार की ओर से बाकी राज्यों के साथ एक अलग-सा व्यवहार हो रहा है और उत्तराखंड और हिमाचन प्रदेश के साथ अलग-सा व्यवहार हो रहा है?

आप जानते हैं उत्तरांखड राज्य का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है और इसका 65 प्रतिशत क्षेत्र विशुद्ध रूप से पर्वतीय है, वनों का क्षेत्र है। आज आप पर्यावरण की बात करते हैं, मै सोचता हूं कि देश के लिए ऑक्सीजन देने वाले पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड राज्य का अग्रिम स्थान है। इस राज्य को एक प्रकार से देवभूमि कहा जाता है। सारे देश के लोग यहां जाते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग यहां जाते हैं। हिमालय की गंगा, यमुना और काली, जिसे शारदा नदी भी कहा जाता है, ये सारे देश के लिए या एक प्रकार से पूरे उत्तर भारत के लिए सिंचाई का काम करती हैं।

आज दिक्कत क्या है? जब उत्तराखंड राज्य बना, उसके छ: महीने के अन्दर राष्ट्रीय विकास परिषद, एन.डी.सी. ने इसको विशेष राज्य का दर्जा भी दिया। इन ग्यारह राज्यों में उत्तराखंड भी एक राज्य है। इसके लिए निश्चित रूप से मैं तत्कालीन सरकार जिसने इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया, धन्यवाद देता हूं। लेकिन 1998 में, जो एन.डी.ए. की तत्कालीन सरकार थी, उसने नॉर्थ-ईस्टर्न राज्यों के लिए एक नियम बनाया। उस नियम के हिसाब से उन्होंने एक Non-Lapsable central pool of Resources (NLCPR) की रचना करके एक प्रकार से इसे स्वीकृति दी। 1998-99 के हमारे तत्कालीन फाइनांस मिनिस्टर की स्पीच में से मैं यह पढ रहा हूं, उन्होने कहा, "Furthermore, it has been decided that a Non-Lapsable Central Pool of Resources will be created for deposit of funds from all Ministries where the Plan expenditure on the North-Eastern Region is less than 10 per cent of